Publication	The Pioneer	Language	English
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	14/04/2023	Page no	2
CCM	40.69		

PACS to get priority in allotment of petrol/diesel dealerships, purchase of ethanol

PIONEER NEWS SERVICE ■
NEW DELHI

Now Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in the country will get priority in allotment of new petrol/diesel dealerships and purchase of ethanol produced by cooperative sugar mills. They will also be able to apply for LPG distributorship and have the option to convert existing Wholesale Consumer Licensed PACS into retail outlets.

This was decided at a meeting held between Union Home Minister Amit Shah and Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri here in the national capital on Wednesday.

The move was taken with an aim to strengthen the PACS as well as pave a way for them to convert into multipurpose economic units, which will provide regular sources of income to crores of farmers of the country and hence realize the goal of 'Sahakar se Samardhi' as envisioned by Prime Minister Narendra Modi. Giving details, a senior official from the Cooperation Ministry said that Ministry of Petroleum and Natural Gas agreed to convert existing wholesale petrol and diesel dealership licensed under Primary Agricultural Credit Societies (PACS) into retail outlets, provided they fulfil all the requirements for setting up retail outlets in rural areas, including statutory approvals and other permissions.

The decision also aims to give priority to PACS in the allotment of new petrol and diesel dealerships. Now, PACS have been made eligible to get LPG distributorship as well.

As per an official from the Union Ministry of Cooperation, the existing PACS will be given a one-time option to convert their wholesale consumer pumps into retail outlets. With the eligibility for LPG distributorship, the PACS will become the economic hub of rural development, the official said, adding that the PACS will become a strong empowered entity after the option to convert existing wholesale consumer-licensed PACS into a retail outlet. In addition to the above, rules will also be changed by the Ministry of Petroleum to make PACS eligible for LPG distributorship.

Also, under the Ethanol Blending Program, the Ministry of Petroleum will ensure that cooperative sugar mills are given priority for ethanol procurement at par with other private companies, explained the officials.

It has also been decided that PACS will be considered under the Combined Category -2(CC 2) along with the freedom fighter and sports quota in the allotment of new petrol/diesel dealerships, he said.

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from
SAMVAD

Publication	Rashtriya Sahara	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	14/04/2023	Page no	11
CCM	79.46		

पेट्रोल/डीजल/एलपीजी डीलरशिप में पैक्स को प्राथमिकता

नई दिल्ली (एसएनबी)। सरकार नए पेट्रोल/डीजल पंप की डीलरशिप के आवंटन में पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समितियां) को प्राथमिकता देगी। अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिल सकेगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और सहकारी क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

इस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत यह सहमति हुई कि सहकारी चीनी मिलों को अन्य निजी कंपनियों के बराबर इथेनॉल की खरीद के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के कवरेज के विस्तार और इसे मजबूत करने में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को पूरा करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, केंद्रीय गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, इससे जुड़े हितधारकों के कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।

बताया गया है कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ जो बैठक की उसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मौजूदा थोक को परिवर्तित करने पर सहमत हो गया।

उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को खुदरा दुकानों में बदलना। इसके तहत, मौजूदा पीएसीएस को अपने थोक उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का एक बार का विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते वे ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा दुकानों की स्थापना के लिए वैधानिक अनुमोदन और अन्य अनुमतियों सहित सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में पैक्स और सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए है।

उपरोक्त के अलावा, पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र बनाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि नए पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन में पैक्स को स्वतंत्रता सेनानी और खेल कोटा के साथ संयुक्त श्रेणी-2 (सीसी 2) के तहत विचार किया जाएगा। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत, पेट्रोलियम मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य निजी कंपनियों के समान

- निर्णय अमित शाह और हरदीप पुरी की बैठक में लिया गया
- सहकारी चीनी मिलों को अन्य निजी कंपनियों के बराबर इथेनॉल की खरीद के लिए प्राथमिकता दी जाएगी

सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल खरीद के लिए प्राथमिकता दी जाए।

देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को मजबूत करने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे कि पैक्स के लिए मॉडल उपनियम। इन मॉडल उपनियमों को स्वीकार करने से देश भर में लगभग एक लाख पैक्स ग्रामीण आर्थिक विकास की धुरी बनेंगे और बहु-आयामी इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगे। वे 25 से अधिक गतिविधियों के माध्यम से देश के 13 करोड़ से अधिक किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। पैक्स के सशक्तिकरण की दिशा में सहकारिता मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत वर्तमान में पैक्स का कम्प्यूटरीकरण चल रहा है, जिससे पैक्स को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ा जा सकेगा।

इसके साथ ही सहकारिता मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए है, जिसके तहत सीएससी की 300 से अधिक ई-सेवाएं देश के लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

पैक्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में सभी पंचायतों/गांवों को कवर करते हुए 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स और प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य भी रखा है। सहकारी समितियों को भी 'खरीदार' के रूप में शामिल किया गया है। पैक्स के स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का विकेंद्रीकरण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों से पैक्स को मजबूत करने के साथ-साथ उन्हें बहुउद्देशीय आर्थिक इकाइयों में बदलने में मदद मिलेगी, जिससे देश के करोड़ों किसानों को आय का नियमित स्रोत मिलेगा। अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के कवरेज के विस्तार और इसे मजबूत करने में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

पैक्स मजबूत होंगे और इनसे जुड़े लोगों की आय में वृद्धि होगी : पैक्स को नए पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे सहकारी आंदोलन को मजबूती मिलेगी। पैक्स ग्रामीण विकास का आर्थिक केंद्र बनेगा। मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने का विकल्प होगा। पैक्स एक मजबूत सशक्त इकाई बन जाएगी। सहकारी चीनी मिलों द्वारा उत्पादित एथेनॉल के क्रय को प्राथमिकता दी जाएगी। पैक्स अब खुदरा दुकानों की स्थापना और संचालन भी कर सकेंगी।

****

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD